

उत्तराखण्ड शासन,  
आवास अनुभाग-2  
संख्या-1702/V-2-2015-67(आ0)2016  
देहरादून: दिनांक 11 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा-5 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के विनियमित क्षेत्रों में एकीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) को अधिसूचना संख्या-2015/V/आ0-2015-55(आ0)/06-टी0सी0 दिनांक 08-12-2015 द्वारा निर्गत किया गया है।

2- उक्त अधिसूचना में भू-उच्चीकरण शुल्क से सम्बन्धित प्रस्तर-3.3 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए निम्न विवरणानुसार संशोधित प्राविधान एतद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

बिन्दु संख्या	भवन उपविधि 2011 (संशोधन 2015) में निहित प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तर 3.3	<p>(vi) तकनीकी अनापत्ति उपरांत आवेदक द्वारा भू-उच्चीकरण शुल्क एवं बाह्य विकास शुल्क निम्न स्थितियों में जमा की जायेगी जिसके उपरांत मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा -</p> <p>ऐसे विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र, जिनकी महायोजना स्वीकृत न होने के कारण भू-उपयोग निर्धारित नहीं है, में सम्बन्धित भूमि को कृषि/अविकसित/बंजर मानते हुए समस्त प्रकरणों का गुण-दोष के आधार पर अनुमन्य होने की स्थिति में भू-उच्चीकरण शुल्क एवं सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाह्य विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा। 250 वर्गमीटर तक के भूखण्डों एवं एकल आवासीय भवनों को छोड़कर सभी प्रकार के प्रयोजन के भवनों पर भू-उच्चीकरण शुल्क देय होगा।</p> <p>जिन क्षेत्रों की महायोजना स्वीकृत है, में सम्बन्धित भू-उपयोग में अनुमन्य निर्माण गतिविधियों का तकनीकी परीक्षणोपरांत तथा स्वीकृति से पूर्व सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाह्य विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा।</p>	<p>तकनीकी अनापत्ति उपरांत आवेदक द्वारा भू-उच्चीकरण शुल्क एवं बाह्य विकास शुल्क निम्न स्थितियों में जमा की जायेगी जिसके उपरांत मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा -</p> <p>ऐसे क्षेत्र जिनमें महायोजना लागू नहीं है, में भू-उच्चीकरण शुल्क निम्नानुसार देय होगा -</p> <p>(1) चूंकि नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र बाहुल्य रूप से निर्मित क्षेत्र स्वरूपीय होता है, अतः भू-उच्चीकरण शुल्क नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत देय नहीं होगा।</p> <p>(2) नगर निकाय सीमा के बाहर के क्षेत्रों में 2000 वर्गमी0 एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्डों को कृषि/अविकसित/बंजर मानते हुए सम्बन्धित भूखण्ड में प्रस्तावित गैर सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधि तथा उच्च तकनीकी संस्थाओं हेतु भू-उच्चीकरण शुल्क देय होगा।</p> <p>(3) भू-उच्चीकरण शुल्क कृषि से प्रस्तावित गतिविधि हेतु निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का आधा होगा।</p> <p>जिन क्षेत्रों की महायोजना स्वीकृत है, में सम्बन्धित भू-उपयोग में अनुमन्य निर्माण गतिविधियों का तकनीकी परीक्षणोपरांत तथा स्वीकृति से पूर्व सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाह्य विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा।</p>

4

2- उक्त अधिसूचना दिनांक 08-12-2015 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव

संख्या- 1702 /V-2-2015-67(आ०)/2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना एवं संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) की प्रति सहित प्रेषित।
- 4- वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- ✓ 5- गार्ड बुक/एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव